

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—श्री इन्द्र सिंह राव आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या— 100 / 2018

बउनवान

प्रभूलाल पुत्र नेनगा जाति—बैरवा निवासी—सीसवाली
तहसील—मोंगरोल जिला—बारां

(अपीलांत)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्गे नायब तहसीलदार, सीसवाली

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :-1. श्री कमलदीप सिंह हाडा, अभिभाषक
2. परोकार सरकार

(अपीलांत)

(रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक— 08.08.2019

अपीलांत ने जर्गे अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली के आदेश दिनांक 16.08.2018 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम—सोनवा, तहसील—मोंगरोल की आराजी खसरा नम्बर 349 रकबा 0.11 हैक्टर किस्म—गै.मु.नहर पर अतिक्रमी मानकर 176 /—रूपये अर्थदण्ड एवं तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं कानूनी मान्यता प्राप्त सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व मौके पर कब्जे बाबत कोई पुष्टि नहीं की, पडौसी खेत वालों की कोई साक्ष्य रेकार्ड पर नहीं लेकर मात्र पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर अपीलांत को सुनवायी एवं जवाबदेही का अवसर दिये बिना एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांत का कोई कब्जा नहीं है व जुर्माना बकाया नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर एकरतफा निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं दंडादेश निरस्त फरमाया जाकर, दोषमुक्त घोषित किया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्गे सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांत व परोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांत ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नहीं देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। अपीलांत का विवादित

आराजी पर कोई कब्जा नहीं है, कब्जा पूर्व से ही छोड़ रखा है। साथ ही निवेदन किया कि अपीलान्त विवादित आराजी पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती बाबत स्वतंत्र गवाहान के बयान एव बेदखलीनाम नहीं है। ऐसी स्थिति में पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त के विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपीलान्त की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.8.2018 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत परोकार सरकार ने अपीलान्त के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलान्त विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर सम्वत् 2075 खरीफ में बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलान्त व परोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्त को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलान्त का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्त के प्रति सहानुभूति व नरमी का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

परिणामस्वरूप, अपीलान्त की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली द्वारा निर्णय दिनांक 16.08.2018 से पारित बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 01/2018 में पारित निर्णय दिनांक 16.08.2018 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलान्त विवादित आराजी से कब्जा छोड़ दें तथा नायब तहसीलदार, सीसवाली के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिंग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा नायब तहसीलदार कब्जा छोड़ने से सन्तुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली द्वारा निर्णय दिनांक 16.08.2018 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली का उक्त निर्णय यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर, बारां

